R.N.I. No. RAJHIN/2019/77793

postal reg.no. RJ/RJ/207/2025/2027

विज्ञापन एवं
वार्षिक सदस्यता
हेतु कार्यकारी
सम्पादक -
सहर
मो. 8107416712

मरूधरा टुडे

पाक्षिक

वर्ष 06 अंक 20 | कुल पृष्ठ 4 | अजमेर, शनिवार 1 फरवरी, 2025 | Email.Id: marudharatoday.info@gmail.com | मूल्य : 3 /- रुपये

विधान सभा में सर्वदलीय बैठक सम्पन्न– विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों को सदन संचालन में सहयोगी बनने का किया आव्हान

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा है कि राजस्थान विधानसभा का यह पवित्र सदन प्रदेश की आठ करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है। सदन की कार्यवाही को आम जनता देखती है। प्रदेश की जनता से चुनकर आये जनप्रतिनिधिगण अपने आचरण और व्यवहार से जन आकांक्षाओं के अनुकूल आदर्श प्रस्तुत करें। श्री देवनानी ने कहा कि विधान सभा सदन नियमों, परम्पराओं व मर्यादाओं से चलता है। उन्होंने सभी दलों से सदन को शांतिपूर्वक चलाने में सहयोग करने और सार्थक बहस में अपनी बात समय सीमा में रखने के लिए कहा है।

सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के तृतीय सत्र की बैठकें शुक्रवार 31 जनवरी से आरम्भ होगी। इससे पहले बुधवार को विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में विधान सभा में सर्वदलीय बैठक सम्पन्न हुई।

विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि सोलहवीं राजस्थान विधान सभा का सदन नये कलेवर में तैयार हो गया है। सदन को वन-नेशन-वन एप्लीकेशन के तहत टेब लगाकर तैयार कर दिया गया है। सदन में सार्थक चर्चा और राज्यपाल अभिभाषण को पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी सदस्यगण शान्तिपूर्ण सुनने के लिए बैठक में सहमती बनी।

देवनानी ने कहा कि सदस्य सदन में मर्यादित व्यवहार करें और वैल में नहीं आएं। सभी सदस्यों को नियमों के अनुसार बोलने का मौका मिलेगा। विधान सभा का सदन अधिक से अधिक दिन चले इसके लिए सभी दलों को सकारात्मक सोच रखनी होगी। उन्होंने कहा कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सोलहवीं विधान सभा के सभी सदस्यों की है।

90 प्रतिशत प्रश्नों के जवाब विधान सभा को प्राप्त हुए- अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि सोलहवीं विधान सभा के 90 प्रतिशत प्रश्नों के जवाब विधान सभा को प्राप्त हो गये है। श्री देवनानी ने कहा कि यह शुभ लक्षण है। शेष रहे प्रश्नों के जवाब भी विधान सभा को शीघ्र प्राप्त हो जाएंगे। बैठक में विधान सभा को 90 प्रतिशत प्रश्नों के जवाब प्राप्त होने के लिए विधान सभा अध्यक्ष द्वारा किये गये प्रयासों की मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा तथा नेता प्रतिपक्ष सहित सभी ने सराहना की।

शालीनता से उठायें मुद्दे, सदन में सभी को मिलेगा बोलने का मौका- विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि सभी दलों को चर्चा के लिए नियमानुसार समय आवंटित किया जायेगा। उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों के मुख्य सचेतक को विधान सभा सदन की समय सीमा के अनुसार ही आसन को बोलने वाले सदस्यों की सूची देनी होगी। समय सीमा में ही सदस्यों को अधिक से अधिक अपनी बात रखनी होगी। उन्होंने कहा कि यह दलों के नेताओं कि जिम्मेदारी होगी कि उनके दल का सदस्य सदन में अपनी बात को आवंटित समय में ही रखने का प्रयास करे। श्री देवनानी ने कहा कि सभी सदस्यगण शालीनता से मुद्दे उठाये।

जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस हो- देवनानी ने कहा कि यह सदन जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने का पवित्र स्थल है। इस स्थल की गरिमा को बनाएँ रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रतिपक्ष अपनी बात रखें। प्रतिपक्ष को नियमों के अनुसार पूरा समय दिया जाएगा। राज्य सरकार भी प्रतिपक्ष द्वारा उठाये गए मुद्दों को गम्भीरता से ले।

स्वस्थ आलोचनाओं से कार्य में आती है नवीन गति-

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सदन में अपनी-अपनी बात रखने के लिए पक्ष व प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों की भावना एक समान ही होती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सदस्यों की बातों को गम्भीरता से लिया जायेगा। सदस्यों द्वारा उठाई गई समस्याओं का निस्तारण भी कराया जायेगा। उन्होनें कहा कि स्वस्थ आलोचनाओं से कार्य में नवीन गति आती है।

संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान विधान सभा में अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की यह ऐतिहासिक पहल है। सदन संचालन में इस सर्वदलीय बैठक के दूरगामी सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। उन्होनें बैठक में उपस्थित होने वाले पक्ष व प्रतिपक्ष के नेतागण का आभार ज्ञापित किया। बैठक में सरकारी मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग] प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक श्री रफीक खान] बसपा के श्री मनोज कुमार और रालोद के डॉ. सुभाष गर्ग भी मौजूद थे।

बैठक में आये महत्वपूर्ण सुझाव- बैठक में सदन में पहले से चल रही पर्ची पर बोलने की व्यवस्था पर मंत्रीगण से जवाब दिलाने पर भी चर्चा हुई। समितियों की रिपोर्ट पर बहस कराये जाने और अधिकारियों की सदन की अधिकारी दीर्घा में उपस्थिति को सुनिश्चित किये जाने के सुझाव भी आये। राजस्थान विधान सभा में सदन चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन श्री देवनानी की ऐतिहासिक पहल है। श्री देवनानी ने सदन को नियमों मर्यादाओं और शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सोलहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी सदस्य सदन में इस तरह का व्यवहार करें कि यह सत्र विधान सभा का आदर्श बन सकें और लोकतंत्र के इस पावन स्थल से आमजन की अपेक्षाएं पूरी हो सके।

मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने विधान सभा पहुंचने पर अध्यक्ष श्री देवनानी का पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनन्दन किया। अध्यक्ष श्री देवनानी ने मुख्यमंत्री श्री शर्मा तथा नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली को राजस्थान विधानसभा का वर्ष 2025 का वॉल एवं टेबल कैलेण्डर भेंट किये। श्री देवनानी ने सभी दलों के नेताओं को सदन के बदले स्वरूप का अवलोकन भी कराया।

मिलावट पर वार अभियान को दे गति

जयपुर। प्रदेश में आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर मिलावट के खिलाफ निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिलों में कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किये जा रहे कार्यों की वीसी के माध्यम से विस्तृत समीक्षा की गई।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशानुसार पूरे राज्य में शुद्ध आहार, मिलावट पर वार अभियान को गति देने के निर्देश दिए गए। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा तथा संयुक्त आयुक्त विजय प्रकाश शर्मा ने अभियान की समीक्षा की। बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को देशभर में प्रथम स्थान पर रहने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रतिमाह आवश्यक सैम्पल लिए जाने एवं निरीक्षण की जानकारी का पोर्टल पर नियमित इंद्राज करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, प्रतिमाह 5 मिस ब्रांडेड के प्रकरण बनाने, मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब का नियमित संचालन करने, ईट राइट गतिविधियों के लक्ष्यों की पूर्ति करने, जिलों में 4 बड़ी कार्रवाई करने एवं न्यायालयों द्वारा निर्णित प्रकरणों में लगाई गयी सजा या शास्ति का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।

3 फरवरी को किया जायेगा सूर्य नमस्कार

जयपुर। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग गत वर्ष की भांति इस बार भी सूर्य नमस्कार में नया विश्व रिकॉर्ड रचने की तैयारी कर रहा है। सूर्य सप्तमी के अवसर पर प्रदेश के सभी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में एक साथ 3 फरवरी, 2025 को सूर्य नमस्कार किया जाएगा। इस दौरान गत वर्ष 78,974 स्कूलों में 1.33 करोड़ विद्यार्थियों द्वारा सूर्य नमस्कार में बने विश्व रिकॉर्ड को ब्रेक करने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा संकुल में हुई एक बैठक में शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने वीसी के जरिए जिला एवं ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सूर्य नमस्कार हमारी भारतीय परंपरा से जुड़ा एक अहम हिस्सा है। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करने से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मन-मष्तिष्क भी शांत रहता है। मैं सूर्य नमस्कार में एक बार फिर विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए आमजन को भी आयोजन का हिस्सा बनाने की अपील की। राज्य के सभी राजकीय एवं गैर राजकीय शिक्षा संस्थानों में एक साथ एक समय पर सूर्य नमस्कार का आयोजन 3 फरवरी, 2025 को सुबह सवा दस बजे किया जाएगा। 20 मिनट के इस कार्यक्रम में सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं गणमान्य व्यक्तियों, एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों एवं आमजन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चत की जाएगी और कार्यक्रम की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करके उसकी रिपोर्ट लेना सुनिश्चत की जाएगी। इस आयोजन का संपूर्ण डेटा शाला दर्पण एवं पीएसपी पोर्टल पर दोपहर दो बजे तक अपलोड किया जाएगा।

वनपाल एवं वनरक्षक 10,000 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार

जयपुर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये रतिपाल सिंह, वनपाल व ओमप्रकाश मिठारवाल, वनरक्षक चन नाका चिमनपुरा, रेन्ज नाहरगढ अभ्यारण्य, जयपुर को 10,000 रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि आरोपी द्वारा परिवादी की दो दुकानों के निमार्ण कार्य में रूकावट नहीं डालने की एवज में 10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस कालुराम रावत के सुपरवीजन में ए.सी.बी स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर के संदीप सारस्वत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में आज मय सुरेन्द्र पंचोली, उप अधीक्षक पुलिस एवं अन्य के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी रतिपाल सिंह, वनपाल व ओमप्रकाश मिठारवाल, वनरक्षक वन नाका चिमनपुरा, रेन्ज नाहरगढ अभ्यारण्य, जयपुर को 10,000 रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

संपादकीय

दलित ओबीसी मतदाता बनाएंगे दिल्ली में सरकार

दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डालने में अब कुछ दिनों का समय ही शेष रह गया है। वहां चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। सभी दलों के बड़े नेता अपनी-अपनी पार्टी प्रत्याशियों को जीताने के लिए जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में चुनावी चौसर बिछी हुई है। सट्टा बाजार में राजनीतिक दलों की हार-जीत के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी इसका पता तो 8 फरवरी को मतगणना के बाद ही चल पाएगा।

मगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) चौथी बार सरकार बनाने के प्रयास में लगी हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भी चाहती है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उनकी पार्टी की सरकार बने ताकि केंद्र व राज्य का झगड़ा समाप्त हो। कहने को तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। यहां की सरकार व मुख्यमंत्री के पास अन्य प्रदेशों की तरह पूरे अधिकार नहीं होते हैं। मगर दिल्ली का मुख्यमंत्री होना अपने आप में बड़ी बात है। दिल्ली से ही देश की सरकार चलती है। ऐसे में दिल्ली में जो सरकार बनती है उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार दलित, जाट व गुर्जर मतदाताओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने जा रही है। दिल्ली में 12 विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहां करीबन 18 प्रतिशत दलित मतदाता है। दिल्ली की आरक्षित 12 सीटों के अलावा 18 और ऐसी विधानसभा सीटे हैं जहां दलित मतदाताओं की संख्या 15 प्रतिशत से अधिक है। ऐसे में दिल्ली की 30 विधानसभा सीटों पर दलित मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है।

दिल्ली में बवाना, सुल्तानपुर माजरा, मंगोलपुरी, करोल बाग, पटेल नगर, मादीपुर, देवली, अंबेडकर नगर, त्रिलोकपुरी, कोंडली, सीमापुरी, गोकलपुर विधानसभा सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा करीबन 15 से 20 अन्य ऐसी सीटें है जहां दलित मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसलिए दिल्ली विधानसभा की 70 में से करीबन 30 सीटों पर दलित मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सभी 12 आरक्षित सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने चुनाव जीता था। इसलिए आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस दलित मतदाताओं पर है। दिल्ली के अनुसूचित जाति के मतदाताओं में से 38 फीसदी जाटव और 21 फीसदी वाल्मीकि है।

पिछले लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के मतदाताओं के लिए देश भर में आरक्षित 84 लोकसभा सीटों में से भाजपा मात्र 30 सीट पर ही चुनाव जीत पाई थी। इंडिया गठबंधन के भाजपा द्वारा संविधान बदलने के नारे के कारण दलित मतदाता भाजपा से छिटककर विपक्षी खेमे में चले गए थे। इसी तरह दिल्ली में भी पिछले दो विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सभी 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी लगातार जीतती आ रही है। इसलिए अनुसूचित जाति के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा व कांग्रेस इस बार के चुनाव में पूरा जोर लगा रही है।

भाजपा ने 12 आरक्षित सीटों के अलावा दो सामान्य सीटों मटिया महल से दीप्ति इंदौरा व बल्लीमारन से कमल बागड़ी को उम्मीदवार बनाया है। इस तरह भाजपा ने कुल 14 सीटो पर दलित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने भी नरेला से अनुसूचित जाति की अरुणा कुमारी को टिकट देखकर कल 13 सीटों पर दलित प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। भाजपा व कांग्रेस की रणनीति है कि दलित मतदाताओं को आम आदमी पार्टी से दूर किया जाए। आम आदमी पार्टी ने 12 आरक्षित सीटों पर ही अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों को टिकट दी है। हरियाणा व महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक बार फिर दलित मतदाताओं का रुझान भाजपा की तरफ होने के चलते वहां भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की थी। इसी से उत्साहित होकर भाजपा अनुसूचित जाति के मतदाताओं की बहुलता वाली सीटों पर विशेष चुनावी प्रबंधन कर चुनावी रणनीति बना रही है। दिल्ली में जाट मतदाताओं की बहुलता वाली 10 सीटों महरौली, मुंडका, रिठाला, नांगलोई, मटियाला, पालम, नरेला, विकासपुरी, नजफगढ़ व बिजवासन पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। इस बार भाजपा आम आदमी पार्टी से इन सभी 10 सीटों को छीन कर अपनी वापसी का प्रयास कर रही है। भाजपा ने इस बार करीबन 14 टिकट जाट नेताओं को दी है। जिनमें पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। वही आप सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे कैलाश गहलोत भी बीजेपी टिकट पर बिजवासन से चुनाव लड़ रहे हैं। कैलाश गहलोत के भाजपा में जाने से आप के पास कोई बड़ा जाट नेता नहीं रह गया है जो जाट मतदाताओं को आप पार्टी से जोड़े रख सके। जबकि भाजपा ने पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा कर दिल्ली के चुनाव को रोचक बना दिया है। दिल्ली में गुर्जर मतदाताओं की भी बड़ी संख्या है। इनके प्रभाव वाली छतरपुर, मुस्तफाबाद, तुगलकाबाद, घोंडा, गोकुलपुरी, ओखला पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। वहीं बदरपुर, करावल नगर व पालम पर भाजपा का कब्जा है। दिल्ली के पूर्व सांसद व बड़े गुर्जर नेता रमेश बिधूड़ी को भाजपा ने मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार कर चुनाव को रोचक बना दिया है। दिल्ली में मदनलाल खुराना व साहिब सिंह वर्मा के बाद हमेशा बाहरी व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनता रहा है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, अतिशी मार्लेना जैसे लोग दिल्ली के मूल निवासी नहीं है। इसलिए दिल्ली के लोग चाहते हैं कि अब की बार दिल्ली का ही रहने वाला नेता दिल्ली का मुख्यमंत्री बने ताकि उसे दिल्ली की असली नब्ज व समस्याओं की बखूबी जानकारी हो। जाट मतदाता चाहते हैं कि साहिब सिंह वर्मा के बाद एक बार फिर उनके बेटे प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाए ताकि दिल्ली का सर्वांगीण विकास हो सके।

वही गुर्जर मतदाता रमेश बिधूड़ी को मुख्यमंत्री बनाने की का मांग कर रहे हैं। कहने को तो कांग्रेस भी पूरी सक्रियता से चुनाव लड़ रही है। मगर इंडिया गठबंधन में उनके साथी दलों द्वारा आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के बाद कांग्रेस का मनोबल कमजोर हुआ है। इसी के चलते कांग्रेस का चुनाव प्रचार भी ज्यादा गति नहीं पकड़ पाया है। ऐसे में मुख्य मुकाबला आप व भाजपा के मध्य माना जा रहा है।

पीएम आवास की लागत फंडिंग 2 लाख करने की मंत्रियों ने रखी अपनी मांग

नई दिल्ली। आम बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट में इजाफ़े की मांग पुरजोर तरीके से दिल्ली की कान तक पहुंची है। मजे की बात ये है कि ज्यादातर भाजपा शासित प्रदेशों की ओर से ऐसी मांग तब सामने आई जब गत दिनों कृषि एवम् ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यों के मंत्रियों के साथ औपचारिक चर्चा कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान का राज्य मध्यप्रदेश हो या फिर मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, बिहार, आंध्र, असम, गुजरात और हरियाणा जैसे भाजपा शासित राज्य हों, सभी की ओर से एकसुर में पीएम आवास योजना के फंड को नाकाफी बताया।

भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों के आवाज में आवाज मिलाने का काम किया झारखंड, पंजाब और तमिलनाडु जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों ने।

सूत्रों ने बताया कि सभी राज्यों के मंत्रियों की राय थी कि वर्ष 2016 के बाद से प्रति यूनिट पीएम आवास योजना के लागत का नये सिरे से मूल्यांकन नहीं किया गया, जबकि 8 सालों में एक यूनिट की लागत में बहुत वृद्धि हुई है। सीमेंट, स्टील, मजदूरी सब बढ़ी है। बैठक में शामिल सूत्रों के बताया कि इस बात पर विशेष चर्चा हुई कि 2016 में मौदानी राज्यों के लिए 1.20 लाख प्रति मकान फंड की स्वीकृति थी जबकि पहाड़ी इलाकों के लिए 1.30 लाख की दर से लागत व्यय करने का तय किया गया था। ये बात अलग है कि पीएम आवास योजना के तहत पहले यही दर 70 हजार और 75 हजार थी।

झारखंड सरकार अबुआ आवास योजना के तहत 2 लाख रुपया लाभार्थी को आवंटित कर रही है। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय ने हरिभूमि से कहा, जब राज्य सरकार दो लाख दे रही है तो उसी मद में पीएम आवास योजना 1 लाख 20 हजार प्रति यूनिट क्यों दे रहे हैं, बढ़ाया ही जाना चाहिए। पीएम आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में गरीबों के लिए 2 करोड़ 95 लाख मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2016 में जिसे गत वर्ष बढ़ा कर 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ पीएम आवास बनाने का नया लक्ष्य रखा गया। इस मद में 54 हजार 500 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया था।

झारखंड की तर्ज पर अब केंद्र पर दबाव है कि 1 लाख 20 हजार प्रति यूनिट पीएम आवास की लागत को बढ़ाकर 2 लाख किया जाए, मंत्रियों की मांग ऐसी ही थी, लेकिन एक साथ इतना बड़ा इजाफा करना आसान नहीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मंत्रियों की मांग को पीएमओ के बरास्ते वित्त मंत्रालय भेजा गया है।

जिसके तहत मैदानी इलाकों के लिए 2 लाख प्रति यूनिट और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 2.25 लाख करने के प्रावधान की अनुशंसा है।

उत्तर विधानसभा क्षेत्र की 5 प्रमुख सड़कें बनेंगी आदर्श सड़कें- विधानसभा अध्यक्ष

सड़कों, नालों की गुणवत्ता मॉनिटरिंग की जांच चीफ इंजीनियर स्तर के अधिकारी से कराने के निर्देश, लोहागल से जनाना अस्पताल तक 4 किलोमीटर बनेगी 100 फीट चौड़ी सड़क

अजमेर/जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को शहर की सड़कों के हालातों की समीक्षा के साथ ही उनकी गुणवत्ता को लेकर सर्किट हाऊस में अन्तर्विभागीय समन्वय बैठक ली। श्री देवनानी ने बैठक में सड़क निर्माण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां व गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु, अजमेर विकास प्राधिकरण आयुक्त नित्या के., नगर निगम आयुक्त श्री देशल दान सहित आरएसआरडीसी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं टाटा पावर के अधिकारी मौजूद रहें। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने उत्तर विधानसभा क्षेत्र की 5 प्रमुख सड़कों को आदर्श सड़क बनाने के निर्देश दिए। यह आदर्श सड़कें स्मार्ट सिटी की तर्ज पर होनी चाहिए जिसमें बेहतर लाईनिंग, खड्डे रहित सड़क और बेहतर रोड लाईट की व्यवस्था होनी चाहिए। इन पांच आदर्श सड़कों में मित्तल हॉस्पीटल से टेलीफोन एक्सचेंज, केन्द्रीय बस स्टैण्ड से एमडीएस तिराहे तक, बीकानेर स्वीट्स वैशाली नगर से माकड़वाली तक, महावीर सर्किल से फॉयसागर झील तक तथा जवाहर रंगमंच से शास्त्री नगर चुंगी चौकी एवं लोहागल होते हुए जनाना हॉस्पीटल तक शामिल होगी। उन्होंने एलीवेटेड रोड़ के नीचे की दोनों तरफ की सड़कों का निर्माण पूरा करने के लिए 8 फरवरी की डेडलाईन दी है। ऐलीवेटेड रोड का पानी नीचे की सड़कों को नुकसान नहीं पहुंचाए। इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं होनी चाहिए। बारिश से नीचे की रोड़ भी क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए। सड़क पर पानी इक्ट्ठा ना हो इस प्रकार ढलान दिया जाए। सड़कों की मोटाई निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिए। देवनानी ने बैठक में आगरा गेट से सोनीजी की नसियां तक ऐलीवेटेड रोड के नीचे सड़क को 10 से 15 फीट चौड़ा करने के लिए डाक विभाग और बीएसएनएल के अधिकारियों को भी निर्देशित किया। इससे पूर्व सड़क को चौड़ा करने को लेकर श्री देवनानी केन्द्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिंया से भी मुलाकात कर चुके है और केन्द्रीय मंत्री की ओर से भी विभाग को निर्देशित किया जा चुका है। बैठक में श्री देवनानी ने अजमेर शहर की प्रमुख सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत अजमेर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम से करवाए जाने के भी निर्देश दिए। साथ ही, जिन भी सड़कों, नालों और अन्य विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया उनकी गुणवत्ता मॉनिटरिंग और जांच चीफ इंजीनियर एवं उच्च अधिकारियों द्वारा स्वयं करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बजट घोषणा के तहत 24 करोड़ की राशि से नालों का निर्माण जल्द शुरू होगा। जिसकी टेंडर फरवरी के दूसरे सप्ताह में खुल जाएंगे। इसके अलावा निगम और प्राधिकरण की ओर से भी 11 करोड़ की लागत से नालों का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने अजमेर शहर में प्रवेश के लिए एक नया मार्ग विकसित करने की दिशा में जनाना अस्पताल से लोहागल तक 4 किलोमीटर लम्बे 100 फीट चौड़ी सड़क निर्माण के भी निर्देश दिए। इस रोड के जरिए जयपुर से अजमेर आने वाले वाहन कायड़ विश्राम स्थली बायपास से सीधा जनाना अस्पताल, लोहागल होते हुए पंचशील और शास्त्री नगर क्षेत्र में पहुंच सकेंगे।

देवनानी से निर्देश मिलने के बाद प्राधिकरण आयुक्त और चीफ इंजीनियर ने मौके पर पहुंच स्थिति का जायजा भी लिया। बैठक में श्री देवनानी ने कई सड़कों के निर्माण कार्य के शुभारम्भ होने के बाद भी अब तक पूर्ण नहीं होने पर भी नाराजगी जताई और इन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इनमें स्टीफन चौराहे से झलकारी बाई स्मारक होते हुए लोहागल रोड़ तक सड़क निर्माण कार्य, फॉयसागर रोड़ नाली निर्माण कार्य लम्बित है। श्री देवनानी ने सड़क निर्माण से जुड़े सभी विभागों को आपस में बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए और इसमें व्यावहारिक बाधा के रूप में पानी की पाईप लाईन एवं विद्युत पोल शिफ्टिंग इत्यादि को भी दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने इस अन्तर्विभागीय समन्वय में किसी भी तरह की दिक्कत आने पर जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु से समन्वय बनाकर समस्या समाधान करने के लिए कहा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा के नए परिवेश का किया अवलोकन

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा में 16वीं विधानसभा के तृतीय सत्र की सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा के नए परिवेश का अवलोकन किया। उन्होंने विधानसभा में हुए डिजिटलाइजेशन सहित अन्य नवाचारों की सराहना की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली, संसदीय कार्यमंत्री श्री जोगाराम पटेल, ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरालाल नागर, मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग सहित विभिन्न दलों के नेता मौजूद रहे।

स्वामी व प्रकाशक महेश चंद रांगेरा द्वारा मुद्रक गोपाल सिंह लबाना, गुरुनानक प्रिंटिंग प्रसे, प्लॉट नम्बर 2, पत्रकार कॉलोनी, कोटड़ा, अजमेर से मुद्रित व कार्यालय जी-7सातवीं मंजिल, गुरु अभय रेडिडेन्सी, पंचशील ब्लॉक, अजमेर से प्रकाशित, सम्पादक -महेश चंद रांगेरा व कार्यकारी सम्पादक-सहर। समस्त विवादों के लिए न्यायिक क्षेत्र अजमेर ही रहेगा। मो. 9929590449, 8107416712, Email.Id: marudharatoday.info@gmail.com

किसान आयोग के अध्यक्ष सी.आर. चौधरी ने किया किसानों से संवाद

अधिक उत्पादन- अच्छी गुणवत्ता के साथ करें खाद्यान्न उत्पादन- चौधरी

अजमेर। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र तबीजी में आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम में राजस्थान राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष श्री सी.आर. चौधरी ने किसानों को अधिक उत्पादन- अच्छी गुणवत्ता को केन्द्र में रखकर खाद्यान्न का उत्पादन करने का आह्वान किया।

राजस्थान राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष श्री सी.आर. चौधरी ने कहा कि वर्तमान में जीवन की गुणवत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इसलिए व्यक्ति उत्तम गुणवत्ता के भोज्य पदार्थ उपयोग लेना पसंद करते है। ?से में किसानों के सामने अच्छी गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थों का अधिक उत्पादन करना एक चुनौती है। इसे स्वीकार करते हुए जैविक खेती तथा प्राकृतिक खेती को अपनाने की आवश्यकता है। विदेशों में खाद्यान्न निर्यात करने पर भी गुणवत्ता को पहले जांचा परखा जाता है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान किसान आयोग सरकार तथा किसानों के मध्य कड़ी का कार्य करता है। किसानों की समस्याओं का निदान कर उनका समाधान सरकार के

माध्यम से करवाने का प्रयास किया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने किसानों की पीड़ा को समझा है।

किसान को अन्नदाता के रूप में विश्व में पहचान दिलाई है। सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को उपज की लागत का डेढ़ गुना मुल्य दिलवाने के लिए संकल्पबद्ध है। इससे किसानों की आय दुगुनी होगी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर डेढ़ गुना तक कर दिया है । बाजरा 1100 से 1975 तथा मूंग 5000 से 6975 रूपए किया गया है । एक फसली क्षेत्रों में पैदा होने वाली फसलों का समर्थन मूल्य तुलनात्मक रूप से अधिक बढ़ाया गया है। किसानों को पर्याप्त उर्वरक लगातार उपलब्ध कराने के लिए सरकार काम कर रही है । किसानों को प्रमाणित बीज ही इस्तेमाल करने चाहिए। किसान अब स्वयं गिरदावरी कर सकते है।

उन्होंने कहा कि पर ड्रॉप मोर क्रोप की अवधारणा पर काम करते हुए खेत का पानी खेत में तथा गांव का पानी गांव में रहे। इसके लिए प्रत्येक खेत में फार्म पौण्ड होना चाहिए। सरकार ने किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पड़ौसी राज्यों के साथ समझौते किए है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को रामजल सेतु के नाम से जाना जा रहा है। इससे आधे राजस्थान को पीने तथा सिंचाई का पानी मिलेगा। शेखावाटी के लिए यमुना का पानी उपलब्ध होगा। अगले पांच वर्ष में इन परियोजनाओं का लाभ किसानों को मिलने लगेगा। देहात अध्यक्ष श्री जीतमल प्रजापत ने कहा कि सरकार किसानों के हित के लिए विभिन्न आयोजन करवा रही है। किसान संवाद के माध्यम से प्राप्त सुझावों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। इन्हें बजट में शामिल करवाने के लिए सरकार को भेजा जाएगा। विभिन्न योजनाओं का अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लें। भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण गुर्जर ने कहा कि किसानों को अनुदान समय पर मिलना चाहिए। संवाद में उपस्थित किसानों ने विभिन्न विषयो पर अपनी बात रखी। इस अवसर पर कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक श्री संजय तनेजा, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. सुनिल घीया, उद्यान विभाग के उपनिदेशक श्री के.पी. सिंह राजावत सहित विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

महाराजा अग्रसेन महिला समिति महाकुंभ पर्व की झांकी सजा भारतीय संस्कृति को जीवंत किया

अजमेर। महाराजा अग्रसेन महिला समिति की वर्ष 2025 की नवीन कार्यकारी की प्रथम बैठक संरक्षक अंजू पंसारी, मीनू मित्तल, कमलेश मंगल व नीलू गुप्ता के नेतृत्व में संपन्न हुई। अध्यक्ष अंशु बंसल, सचिव सरोज बंसल व कोषाध्यक्ष आशा अग्रवाल के अनुसार महाकुंभ पर्व से महिलाओं को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराने का एक यह अनोखा अंदाज था। इस अवसर पर संस्था संरक्षक द्वारा महिला सशक्तिकरण पर प्रसन्नता व्यक्त की गई समाज में महिलाओं को भारतीय संस्कृति को ऐसे ही जीवंत रखने पर जोर दिया गया । इस अवसर पर विशेष कार्यकारिणी सदस्य दीपिका श्रीया, सुनीता बंसल सहसचिव पूनम खेतावत, उपाध्यक्ष प्रिया मंगल भी उपस्थित रहे । समस्त कार्यकारिणी सदस्य व महिलाओं ने इसी थीम पर रंगारंग हाउजी व गेम्स खेले। गेम्स के विजेता ममता मनोज अग्रवाल व ममता विजय रहे। अंत में भोजन के लुत्फ़ के साथ सभा समाप्त हुई।

पर्यावरण एवं वन राज्यमंत्री ने अलवर के कृषि अनुसंधान केंद्र में इनपुट डीलर्स के 1 वर्षीय डिप्लोमा दीक्षांत समारोह व नए बैच के शुभारंभ कार्यक्रम में की शिरकत प्रशिक्षणार्थियों का किया उत्साहवर्धन, कृषि क्षेत्र में नित नए प्रयोगों के लिए कृषि वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त किया कृषि क्षेत्र में हो रहे नवाचारों में कृषि वैज्ञानिकों का विशेष योगदान - मंत्री श्री शर्मा

जयपुर। पर्यावरण एवं वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय शर्मा ने मंगलवार को अलवर के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विज्ञान केंद्र नौगावा में आदान विक्रेताओं के एक वर्षीय डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर्स के दीक्षांत समारोह व नए बैच के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मंत्री श्री शर्मा ने प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि देश के अन्नदाता को मजबूती प्रदान करना केंद्र व राज्य सरकार की प्राथमिकता है और भजनलाल सरकार द्वारा इसी प्रतिबद्धता को साकार करते हुए कृषकों को निरंतर कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ प्रदान किया जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण केंद्र में जिन प्रशिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है इसका निश्चित रूप से किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आदान विक्रेताओं का भारत को खाद्यान्न में अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है एवं आदान विक्रेता पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा कृषि के क्षेत्र में किए गए प्रयोगों का ही परिणाम है कि वर्तमान समय में भारत खाद्यान का निर्यात अन्य देशों को भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि यहां आकर देखा कि अनुसंधान केंद्र द्वारा मुर्गीपालन, बकरी पालन, उन्नत देशी नसल की गायों का लालन-पालन जिस प्रकार से किया जा रहा है, यह भी एक सराहनीय कदम है।

उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रदेश के किसानों के खातों में एक वर्ष में तीन किश्तों के माध्यम से 6 हजार रूपये देकर

आर्थिक रूप से संबल प्रदान किया तथा इसमें वृद्धि करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 2 हजार रूपये बढ़ाकर किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पीएम मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं से कृषकों की उपज बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का भी आधुनिक खेती व जल संरक्षण को बढावा देने के लिए उठाए गए कदमों के लिए साधुवाद दिया।

कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉ सुभाष चंद्र यादव ने पाठ्यक्रम की महत्ता बताते हुए कृषि के क्षेत्र में आदान विक्रेताओं के योगदान में बारे में बताया। उन्होंने आदान विक्रेताओं से आग्रह किया की आप सभी किसान भाइयों के सीधे संपर्क में है इसलिए आप इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के उपरांत विभिन्न रसायनों के उचित उपयोग हेतु जानकारी देने में सक्षम रहेंगे साथ ही नए बैच के प्रतिभागियों को बताया की ये डिप्लोमा कोर्स आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृषि महाविद्यालय नौगांवा की अधिष्ठाता डॉ. सुमन खंडेलवाल ने सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया एवं सभी को डिप्लोमा कोर्स के लिए शुभकामनाएं दी।

पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा के परिसर में प्रतिदिन पौधारोपण के संकल्प के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति हमें शुद्ध हवा व शुद्ध वातावरण देने का काम करती है, इसलिए हमारा भी प्रकृति के प्रति कर्तव्य बनता है कि इसका संरक्षण करें। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि प्रकृति के संरक्षण के लिए नैतिक कर्तव्य निर्वहन करते हुए एक पेड अवश्य लगाएं।

इस दौरान श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशक

किसान आयोग अध्यक्ष सी.आर. चौधरी ने ली समीक्षा बैठक

जिला स्तरीय कृषि एवं संबद्ध विभागों के कार्यों की हुई समीक्षा

अजमेर। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र तबीजी में राजस्थान राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष श्री सी.आर. चौधरी ने कृषि एवं संबद्ध विभागों के कार्यो की समीक्षा की।

राजस्थान राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष श्री सी.आर.चौधरी द्वारा की गई समीक्षा में कृषि क्षेत्र से जुड़े जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। जिले में विभिन्न योजनाओं में प्रगति की समीक्षा की गई। किसान हित को केन्द्र में रखकर कार्य करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए गए। सरकार द्वारा किसान हित में चलाई जा रही योजनाओं को धरातल पर लागू करने में अधिकारियों का महत्व है। अधिकारी पूरे उत्साह के साथ प्रत्येक पात्र किसान तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्रीअन्न को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य हाथ में लिए है। इनके माध्यम से स्थानीय किसानों की आय में वृद्धि होगी। किसानों को मिलने वाली सब्सीडी के आवेदन लगातार ऑनलाईन एप्रूव होते रहने से पेन्डेन्सी नहीं रहेगी। इसी प्रकार सब्सीडी की फाइले भी जांच उपरान्त आगे बढ़ाई जाए। किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। बैठक में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक श्री संजय तनेजा ने फार्म पौण्ड, सिंचाई पाईप लाईन, तारबन्दी, कृषि यंत्र, बीज उत्पादन एवं वितरण, राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया। आत्मा परियोजना निदेशक श्रीमती उषा चितारा द्वारा कृषक प्रशिक्षण, भ्रमण, कृषक पुरस्कार संबन्धित उपलब्धियों की जानकारी दी गई। उद्यान विभाग के उप निदेशक श्री के.पी. सिंह राजावत द्वारा उद्यान विभाग में कार्यरत प्रमुख गतिविधियां सौलर पम्प संयंत्र, फव्वारा, ड्रिप एवं मिनि फव्वारा, ग्रीन हाऊस, शेडनेट हाऊस, लॉ टनल, प्लास्टिक मल्च, सामुदायिक जल स्त्रोत, फल बगीचा स्थापना, प्याज भण्डारण एवं पैक हाऊस से अवगत करवाया गया। पशुपालन विभाग से डॉ. सुनिल घीया द्वारा पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजना, टीकाकरण, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान, गौशाला अनुदान एवं मंगला पशुधन योजना इत्यादि संबंधित जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केन्द्र से डॉ. धर्मेन्द्र भाटी द्वारा प्रगति से अवगत कराते हुए गई। डॉ. दिनेश अरोड़ा कृषि अनुसंधान तबीजी केन्द्र अजमेर की प्रगति से अवगत कराया एवं केन्द्र तबीजी गांव के अनुसंधान केन्द्र के पीछे से गुजर रहे नालों का पक्का निर्माण करवाकर, कृषकों की भूमि में लवणता एवं क्षारियता की समस्या से अवगत कराया।

डॉ. मनोज कुमार शर्मा उपनिदेशक द्वारा संयुक्त परीक्षण केन्द्र लगाए गए कमल की जानकारी दी गई। श्री रामलाल चौधरी डेयरी विभाग से दुग्ध उत्पादक को उद्योग का दर्जा देने की मुख्यमंत्री कृषक साक्षी सहायता योजना, महात्मा ज्योतिबा फूल मण्डी कृत्रिम कल्याण योजना एवं किसान कलेवा योजना संबन्धित जानकारी दी। श्री राजीव कनौत उप रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग द्वारा अल्पकालीन ऋण योजना संबंधित जानकारी दी गई। श्रीमती शिल्पी जैन जिला विकास प्रबन्धक नाबार्ड द्वारा नार्बाड संबंधित योजनाएं एवं स्वयं सहायता समूह, एफपीओ एवं विभिन्न महत्वपूर्ण संघटनों पर प्रकाश डाला।

स्वच्छता सर्वेक्षण में सुधारें रेटिंग-जिला कलक्टर लोक बन्धु

अजमेर। स्वच्छता सर्वेक्षण में रेटिंग सुधारने के लिए जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु द्वारा नगरीय निकायों के अधिकारियों की बैठक में निर्देश प्रदान किए गए।

जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में रेटिंग सुधारने के लिए समस्त नगरीय निकायों के अधिकारियों को विशेष कार्य करने की आवश्यकता है। सफाई कार्य का परिणाम क्षेत्र में दिखना आवश्यक है। इसके लिए समस्त अधिकारी स्वयं मौके पर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे। व्यस्त बाजारों एवं व्यावसायिक स्थलों पर रात्री पारी में भी सफाई की जाए। सफाई की सीधी मॉनिटरिंग करने के साथ क्षेत्र से भी लगातार फीडबैक लिया जाए।

उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों का सौन्दर्यकरण भी किया जाना चाहिए। यह कार्य भामाशाहों के सहयोग से आसानी से हो जाएगा। नगरीय निकायों के ऑनलाईन कार्यों के बकाया प्रकरण तत्काल प्रभाव से निस्तारित किए जाएं। दो माह से अधिक पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित करें। पट्टे संबंधी प्रकरणों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस कार्य में तेजी लाने के लिए सूचीबद्ध आर्किटेक्ट की पाक्षिक बैठक ली जाए। भवन निर्माण की स्वीकृति भी नियमानुसार जारी होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि म्यूटेशन के प्रकरणों का सात दिन में निस्तारण करें। विधानसभा प्रश्नों के उत्तर तत्काल भिजवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाए। विधानसभा सत्र चलने तक मुख्यालय कर्मचारी सक्षम स्तर से अनुमति लेने पर ही छोड़ेंगे। नगरीय क्षेत्रों में निर्धारित श्रेणी के अनुसार यूजर चार्ज की वसूली नियमानुसार की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि रैन बसेरों एवं अन्नपूर्णा रसोई की नियमित अंतराल से जांच करें। रैन बसेरों में आवश्यक सामग्री उपलब्ध रहनी चाहिए। अन्नपूर्णा रसोई में निर्धारित मीनू के अनुसार तथा निर्धारित मात्रा में भोजन मिले। यहां सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सार्वजनिक शौचालयों की भी नियमित सफाई करावे। पुष्कर सरोवर पर स्थापित चेंजिंग रूम का भी नियमित रखरखाव हो।

इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री देशल दान, अतिरिक्त जिला कलक्टर ज्योति ककवानी, स्थानीय निकाय विभाग की उप निदेशक सना सिद्दकी, किशनगढ़, पुष्कर, ब्यावर, केकड़ी, सावर, सरवाड़, टांटोटी एवं बिजयनगर नगरीय निकायों के अधिकारी उपस्थित रहे।

रसद विभाग ने किए 10 सिलेण्डर जब्त

अजमेर। रसद विभाग द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के अवैध उपयोग की शिकायत मिलने पर आनसागर चौकी के पीछे भट्टे वाली गली क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेण्डरों की धरपकड़ का अभियान चलाया गया।

बुधवार को जांच दल द्वारा 10 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 3 रिफिलींग मशीन जब्त की गई।

जिला रसद अधिकारी श्री नरेन्द्र जैन ने बताया कि आनासागर चौकी के पीछे, भट्टे वाली गली में परवेज पुत्र सिराजुद्दीन के यहां से 5 घरेलू, 3 कर्मीशयल व 2 रिफिलिंग मशीन तथा राकेश यादव के यहां से एक घरेलू, एक कर्मीशयल व एक रिफिलिंग मशीन जब्त की।

इन फर्मो का यह कृत्य एलपीजी ऑर्डर-2000 का उल्लंघन है। साथ ही ये प्रकरण ईसी एक्ट 1955 की धारा 6 ए में जिला कलक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे।

जांच दल में जिला रसद अधिकारी (प्रथम) श्रीमती रतन कौर, संभाग उपभोक्ता संरक्षण अधिकरी श्री भंवर सिंह राठौड़, प्रवर्तन अधिकारी श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन निरीक्षक श्री अतुल बडाया एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी श्री आमोद शुक्ला शामिल रहे।

जिला स्तरीय कौशल प्रादर्श प्रतियोगिता में रक्षा रही प्रथम

ब्यावर, (हेमन्त साहू)। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अजमेर द्वारा आयोजित जिला स्तरीय कौशल प्रादर्श मॉडल प्रतियोगिता में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जवाजा की रक्षा कक्षा 11 में व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड ब्यूटी एंड वैलनेस में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया प्रभारी मीरा गंगवाल, हंसा का विशेष सहयोग रहा। प्रधानाचार्य गुरु शरण गोयल एवं विद्यालय परिवार ने विद्यालय में भी स्वागत अभिनंदन किया तथा बालिका की प्रतिभा पर हर्ष व्यक्त कर शुभकामना व्यक्त की इस अवसर पर विद्यालय परिवार एवं स्टाफ मौजूद रहा।

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024

प्रशिक्षण के संबंध में बैठक आयोजित, 100 मीटर क्षेत्र में रहेंगे ई-मित्र बन्द

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 2 फरवरी को दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक एक पारी में 127 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होने वाली राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 के संबंध में परीक्षा कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं केन्द्राधीक्षक, पर्यवेक्षक एवं उपसमन्वयक दलों को प्रशिक्षण देने के लिए जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु की अध्यक्षता में बुधवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें परीक्षा केन्द्र से 100 मीटर क्षेत्र में ई-मित्र एवं साइबर कैफे बन्द करवाने के निर्देश दिए गए।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं नोडल अधिकारी परीक्षा श्रीमती वन्दना खोरवाल ने बताया कि राजस्थान राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 2 फरवरी को दोपहर 12 से दोपहर 3 बजे तक एक पारी में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होगी। इसके सफल, निष्पक्ष एवं सुचितापूर्ण आयोजन के लिए जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु की अध्यक्षता में प्रशिक्षण बैठक आयोजित की गई। प्रशिक्षण श्री नन्दकिशोर प्रजापति द्वारा दिया गया। जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु ने कहा कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 के संबंध में परीक्षा कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं केन्द्राधीक्षक, पर्यवेक्षक एवं उपसमन्वयक दलों के प्रशिक्षण सत्र में राजस्थान लोक सेवा आयोग की सम्पूर्ण गाईड लाईन के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। राज्य सरकार परीक्षा को सुचिता के साथ आयोजित करवाने के लिए गम्भीर है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वीसी के माध्यम से राज्य के समस्त जिला कलक्टर्स एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ विस्तृत चर्चा की है। परीक्षा के दौरान लापरवाही एवं असंवैधानिक कृत्य करने वालों पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा आयोजन में सहभागिता प्रदान कर रहे समस्त विभागों द्वारा भी नियन्त्रण कक्ष स्थापित किए गए है। ये विभागीय नियन्त्रण कक्ष जिला स्तरीय नियन्त्रण कक्ष 0145-2422517 से लगातार सम्पर्क में रहेंगे। नियन्त्रण कक्ष लगातार कार्यरत रहेंगे।

परीक्षा आयोजन के संबंध में किसी प्रकार की शंका एवं बाधा होने पर स्वयं के स्तर पर निर्णय लेने के स्थान पर आयोग, परीक्षा शाखा अथवा नियन्त्रण कक्ष से सम्पर्क किया जा सकता है। नोडल अधिकारी परीक्षा भी हमेशा उपलब्ध है। प्रत्येक परीक्षा को एक नई चुनौति मानते हुए निर्धारित प्रोटोकॉल, प्रक्रिया एवं निर्देशिका का पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र से 100 मीटर के क्षेत्र में स्थित समस्त साईबर कैफे एवं ई-मित्र को परीक्षा के दौरान बन्द करवाने के निर्देश जारी हुए है। परीक्षा केन्द्रों पर मोबाईल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूर्णतया वर्जित रहेंगे। यहां नियोजित होने वाले स्टाफ आदि के मोबाईल को स्वीच ऑफ करके अलमारी में सील करके रखा जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा केन्द्र में पुलिस कार्मिक को भी मोबाईल लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रवेश पत्र पर अभ्यर्थी का अंग्रेजी एवं हिन्दी में हस्तलेख का नमूना लेना आवश्यक है। परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों एवं कार्मिकों की एचएचएमडी अथवा डीएफएमडी के माध्यम से फिस्किंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को प्रवेश अभ्यर्थी सत्यापन प्रपत्र, मूल आधार कार्ड एवं प्रवेश पत्र की समुचित जांच के उपरान्त ही दिया जाएगा। अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र एवं उपस्थिति पत्र में फॉटो तथा हस्ताक्षर में अन्तर होने पर केन्द्राधीक्षक द्वारा रिपोर्ट में उल्लेख किया जाएगा। अभ्यर्थी के अंगुठे का निशान एवं हस्तलेख का नमूना प्रवेश पत्र पर अनिवार्य रूप से लिया जाए। परीक्षा समाप्ति से पूर्व किसी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र छोड़ने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों एवं परीक्षा केन्द्रों पर वीडियोग्राफी के लिए प्रत्येक केन्द्र पर 2-2 वीडियोग्राफर लगाए जाएंगे। वीडियोग्राफर रिकॉर्डिंग प्रारम्भ करने से पूर्व परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश के दौरान परीक्षा केन्द्र का नाम मुख्य द्वार के साईन बोर्ड से रिकॉर्ड करते हुए एवं परीक्षा केन्द्र का नाम, परीक्षा की दिनांक एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के समय की घोषणा करते हुए रिकॉर्डिंग प्रारम्भ की जाए। वीडियोग्राफी में कक्ष संख्या, रूम चार्ट, अभ्यर्थी के रोल नम्बर बैठक व्यवस्था अनुसार चेहरे की रिकॉर्डिंग एवं टाईम स्टाम्प डालकर करवाई जाए। इससे अभ्यर्थी की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में जिले में 127 परीक्षा केन्द्रों पर 43 हजार 99 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। अजमेर जिला मुख्यालय पर 102 परीक्षा केन्द्र है। इनमें से 32 सरकारी तथा 70 निजी विद्यालय है। इन पर 35 हजार 184 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। किशनगढ़ के 11 परीक्षा केन्द्रों से 4 सरकारी है। यहां 4 हजार 32 अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र आवंटित हुए है। इसी प्रकार केकड़ी में 14 परीक्षा केन्द्रों पर 3 हजार 883 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के लिए जिले में 43 उप समन्वयक दल तथा 22 सतर्कता दल गठित किए गए हैं। सरकारी परीक्षा केन्द्रों पर 50 प्रतिशत अभिजागर एवं निजी परीक्षा केन्द्रों पर 75 प्रतिशत अभिजागर राजकीय सेवा के कार्मिक होंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में साधारण गर्म कपड़े एवं शूज पहनकर बैठने की अनुमति प्रदान की गई है। अत: परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश दिये जाने से पूर्व परीक्षार्थियों की गहन सुरक्षा जाँच किये जाने के निर्देश प्रदान किए गए। अभ्यर्थी को उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी होगी एवं आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी। अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा केन्द्र पर सफेदा, व्हाईटनर एवं करेक्शन पैन लाना पूर्णतया निषिद्ध है। परीक्षा से दो दिवस पूर्व सभी परीक्षा केन्द्रों को खुला रखने के लिए केन्द्राधीक्षकों एवं संस्था प्रधानों को पाबन्द किया गया।